

भाग-1

मिशन मास्टर प्लान

राजस्थान आवासन मंडल के वृत्त तृतीय में स्थित
शोपिंग सेंटर, इंदिरा गाँधी नगर, जगतपुरा
पर बन गया अवैध कामप्लेक्स!!!

प्रथम सूचना रिपोर्ट

1.	भूखंडो का पता	शोपिंग सेंटर, इंदिरा गाँधी नगर, जगतपुरा जयपुर
2.	उल्लंघन की संभावित प्रकृति	बेसमेंट सहित 6 मंजिला अवैध कामप्लेक्स का निर्माण
3.	बिल्डर/सम्बंधित फार्म	नामालूम
4.	सम्बंधित ज़ोन	राजस्थान आवासन मंडल, वृत्त तृतीय
5.	कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारी	नामालूम
6.	सक्षम अधिकारी को शिकायत प्रेषण दिनांक	12/03/2021

जवाब मांगते सवाल?

1. यह कामप्लेक्स वैध है या अवैध?
2. भवन मालिक द्वारा किसकी अनुमति से इस अवैध कामप्लेक्स का निर्माण करवाया गया है? क्या इस अवैध कामप्लेक्स के नक्शे पास है?
3. आखिर कब आवासन मंडल के अधिकारी इन अवैध दुकानों पर बुलडोजर चलाएंगे?
4. यह मामला हमारे द्वारा आवासन मंडल के आला अधिकारियों के संज्ञान में लाने के बावजूद यदि कोई कार्यवाही नहीं होती है और बिल्डिंग के अवैध निर्माण को आंच नहीं आती तो क्या आवासन मंडल के जिम्मेदार अधिकारियों का यह आचरण भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं आता है?
5. क्या आवासन मंडल के जिम्मेदार अधिकारी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट पिटीशन 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राजस्थान सरकार; में दिए गए आदेशों की अवमानना के दोषी नहीं है?
6. क्या इस अवैध निर्माणों के विरुद्ध आज दिनांक तक कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है? क्यों उन शिकायतों पर आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी?

अवैध निर्माण नहीं रोकना भी भ्रष्टाचार

उच्च न्यायालय ने दिखाई सख्ती

जयपुर @ पत्रिका . अवैध निर्माण सहित अन्य अवैध गतिविधियां नहीं रोकने वाले लोकसेवकों पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत कार्रवाई का रास्ता खुल गया है। हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण सहित अन्य अवैध गतिविधियों पर सख्ती दिखाते हुए सोमवार को भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तबरे के बारे में जानकारी के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिरीक्षक एमएन को तलब किया। कोर्ट ने 20 अप्रैल को जयपुर विकास प्राधिकरण आवृत्त, नगर निगम आवृत्त को तलब किया है।

जज महेश चन्द्र शर्मा ने मोहनलाल नामा की अवमानना याचिका पर यह आदेश दिया। हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण मामले में 22 जनवरी 2015 को अप्पॉइंटमेंट देने का आदेश दिया था। इस पर कार्रवाई न होने पर यह याचिका तबरे की है। प्राचीनता की ओर से अधिवक्ता विमल चौधरी ने कोर्ट को बताया कि जयपुर शहर में अवैध निर्माण व कब्जे हो रहे हैं। कोर्ट के आदेशों की अवमानना हो रही है। अवैध निर्माण व कब्जों को रोकने के लिए राज्य सरकार ने अधिकारियों को क्षेत्रवार जिम्मेदारी दी है। कोर्ट ने इस

पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि इन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है या नहीं? जवाब के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिरीक्षक दिनेश एम एन को तलब किया। उन्होंने दायित्व के प्रति अनदेखी को भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में माना।

कार्रवाई संभव

अतिरिक्त महाधिवक्ता जी एस गिल ने कहा कि अवैध निर्माण या अवैध गतिविधियां रोकने के लिए जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी जानबूझकर कार्रवाई न करे या अनदेखी करे तो उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। इसके लिए प्रक्रिया अपनायी होगी। गिल के आग्रह पर कोर्ट ने आदेश जारी करने से पहले जयपुर विकास प्राधिकरण आवृत्त व जयपुर नगर निगम आवृत्त से जवाब तलब किया जाए।

सुनवाई 20 को

कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कोई भी अधिवक्ता पक्ष रखना चाहे तो वह सुनवाई के दौरान पक्ष रखने को स्वतंत्र होगा। मामले की सुनवाई अब 20 अप्रैल को सुबह 11 बजे होगी।

केन्द्रीय सरकार की मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मिडिया आचार संहिता के तहत जारी:- www.jawabdosarkar.com शासन के विभिन्न अभिकरणों में पारदर्शिता और जवाबदेही को प्रोत्साहित करने हेतु स्थापित ऑनलाइन मिडिया प्लेटफार्म है। अपने उत्तरदायित्वों की पूर्ति हेतु पोर्टल द्वारा समय समय पर अपने अभियानों के माध्यम से विभिन्न विषयों / मुद्दों/ समस्याओं के सम्बन्ध में तथ्यपरक रिपोर्ट्स का प्रकाशन किया जाता है। पोर्टल द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट्स को उससे सम्बंधित सभी पक्षों / प्रभावितों और व्यापक जन हित में अधिकतम व्यक्तियों तक पहुंचाना पोर्टल की पारदर्शिता निति का हिस्सा मात्र है। पोर्टल द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट्स का किसी व्यक्ति/ संस्था/ जाति/धर्म / संप्रदाय विशेष से कोई सम्बन्ध नहीं है। पोर्टल द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट्स के सम्बन्ध में अपना पक्ष/ सुझाव/ आपत्तिमय सम्बंधित तथ्यों/ दस्तावेजों के पोर्टल के आधिकारिक पते:- S-1, सेकंड फ्लोर, झारखण्ड अपार्टमेंट, जनरल सगत सिंह मोड़ खातीपुरा रोड, जयपुर अथवा ईमेल:- jawabdosarkar01@gmail.com अथवा व्हाट्सअप न. 9828346151 पर प्रेषित कर सकते हैं। आपके पक्ष/ सुझाव/ आपत्ति को उचित होने पर इस रिपोर्ट के अगले अंक में प्रकाशित कर दिया जायेगा।